Supply of drinking water to the problem villages has been included in the new 20 Point Programme. During the sixth Plan, the effort will be to cover all the identified problem villages with atleast one source of safe potable water available throughout the year. The needs of the scheduled castes and scheduled tribes population in the rural areas will be given due priority in the implementation of this programme. The outlay for the programme in the Sixth Five Year Plan has been stepped upto Rs. 2007.11 crores compared to Rs. 429.27 crores in the Fifth Plan (1974—79).

Additional Irrigation Target for the Sixth Plan

60. SHRI JAIPAL SINGH KASHYAP:

SWAMY INDERVESH:

Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the additional irrigation target planned for the Sixth Plan is not likely to be achieved; and

(b) if so, what is the anticipated shortfall in the achievement of irrigation target during the Sixth Plan period and what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRODHA): (a) and (b) Against a target of 13.74 million hectares, during the first three years of the Plan, 7.06 million hectares of potential are expected to be created upto June 1983. With the same rate of achievement in the remaining two years, a further potential of 4.7 million hectares may be expected in the remaining two years of the Plan. Thus the likely shortfall will be about 2 million hectares.

The main reason for the shortfall is financial constraints due to the escalation in the costs.

Administartive and Financial problems of Slum Improvemenct Schemes

61. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the slums improvement schemes have not met any progress due to legal and administrative problems and financial shortcomings; and

(b) what steps are proposed to speedily implement the slums improvement schemes?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) The reasons for slow progress in the implementation of the scheme for Environmental Improvement of urban slums include shortcomings in the adequate provision of funds, institutional arrangements, involvement of the community, effective monitoring, building materials supply and maintenance of the assets created. The State Governments|UT administrations have been requested to take necessary steps in order to accelerate the implementation of the programme and achieve the targets fixed. 'Slum Improvement' being in the State sector, it is for the State Governments to take suitable remedial measures. The scheme is being constantly monitored by the Central Government under the 20-Point Programme.

विभिन्न राज्यों में गन्ने का अलग-अलग मूल्य ढांचा

62. श्री जगपाल सिंह :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी गन्ना-उत्पादक राज्य में गन्ने का मूल्य 25 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं और यदि विभिन्न राज्यों में विभिन्न मूल्य निर्धारित किये गये हैं तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार खुली बिक्री के लिये और अधिक चीनी का कोटा जारी करने की अपनी वर्तमान नीति को बदलने/पुनरीक्षण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं और इन निर्णयों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि गन्ने का मूल्य 25/– रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के बारे में कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है इसलिए 25/– रूपये के मूल्य के बारे में किन्हीं कठिनाइयों के होने अथवा न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित और केन्द्रीय सरकार को सूचित गन्ने के मूल्य संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

(ग) और (घ) खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटे की मात्रा, उपलब्धता, मांग/आवश्यकता, मूल्य प्रवृत्ति और गुड़ तथा खंडसारी जैसे अन्य स्वीटनिंग एजेंट्स की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जनवरी और फरवरी, 1983 के खुली बिक्री के कोटे को कम करके क्रमश: 2.50 लाख मीटरी टन और 2.00 लाख मीटरी टन कर दिया गया है जबकि नवम्बर, 1982 के लिए 3.20 लाख मीटरी टन और दिसम्बर, 1982 के लिए 3 लाख मीटरी टन की निर्मुक्ति की गई थी ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित और केन्द्रीय सरकार को सूचित गन्ने के मूल्य के रेंज को बताने वाला विवरण

राज्य	(आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल) मौसम 1982-83	
1 पश्चिम उत्तर प्रदेश	21.50	
2 मध्य उत्तर प्रदेश	21.50	
3 पूर्वी उत्तर प्रदेश	20.50	
4 बिहार	20.50	
5 महाराष्ट्र	15.80	(आरम्भिक अग्रिम)
6. आंध्र प्रदेश	18.50	8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर
7 केरल	17.00 से 20.00	
8 पाण्डिचेरी	14.38	
9 पंजाब	20.00	(अनन्तिम) (बढ़िया किस्म के लिए 22/– रुपये)

नर्मदा बांध सिंचाई परियोजना

63. **श्री छोटू भाई गामित :**
श्री नरसिंह मकवाना :
श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नर्मदा बांध सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए कितना समय निर्धारित किया है ;